जैव ऊर्जा की ओर बढ़ाएं कदम, इकाई स्थापना के लिए मिलेगा अनुदान

नई नीति से किसानों की आय में होगी वृद्धि, बैठक में जिलाधिकारी ने दी जानकारी

संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। कृषि और पशुधन अपशिष्ट के उपयोग से किसानों की आय में वृद्धि तो होगी ही साथ ही खेतों में पराली जलाए जाने की समस्या से निदान होगा। इसके लिए इकाई स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। यह जानकारी डीएम अविनाश कुमार ने उप्र सरकार जैव नीति 2022 के तहत बैठक में दी।

जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि और पशुधन अपशिष्ट के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन का विशेष योगदान है। वहीं, ठोस अपशिष्ट के साथ जैव अपशिष्ट का उपयोग करके बायो गैस प्लांट बायोकोल, बायोडीजल, बायो एथनॉल इकाइयों की स्थापना का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसका पहला फायदा यह है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तो दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ेगी। रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र के लिए 75 लाख रुपये प्रति टन की दर से, बायोकोल उत्पादन संयंत्रों के लिए 75 हजार रुपये प्रतिटन की दर से और बायोडीजल उत्पादन संयंत्रों के लिए 3 लाख रुपये प्रति किलोलीटर की दर से 20 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, सभी स्थापित संयंत्रों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भूमि अधिग्रहण पर भी शत प्रतिशत छूट मिलेगी।

बायो एनर्जी संयंत्रों की स्थापना के लिए ग्राम सभा की भूमि पर एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 साल के लिए पट्टे पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए यूपीनेडा को नोडल एजेंसी नामित किया है। इस दौरान प्राप्त 10 आवेदनों पर चर्चा हुई।

आदित्य शर्मा वैद्यनाथ ग्रुप द्वारा चिरगांव के ग्राम लुहरघाट के पास नैपियर घास का उत्पादन कर बायोगैस/सीबीजी का प्लांट तैयार किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में सीडीओ जुनैद अहमद, उप कृषि निदेशक एमपी सिंह, पीओ नेडा वीरेंद्र कुमार जैन, एक्सईएन रमाकांत दीक्षित सहित एफपीओ के किसान मौजूद रहे।

गांव-गांव तक पहुंचाएं पीएम सूर्य घर योजना का लाभ, ब्लॉक स्तर पर लगेंगे कैंप

झांसी। प्रत्येक गांव-गांव के घर-घर तक पीएम सूर्य घर योजना का लाभ पहुंचाने और बिजली की समस्या का निदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित करने का निर्देश डीएम अविनाश कुमार ने दिया। वह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को उपभोक्ताओं की सूची वेंडर्स को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि समय पर पंजीकरण कराते हुए इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जो बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं, उन्हें चिह्नित कर उनका आवेदन कराएं। बैठक में नेडा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि जनपद को 50 हजार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष अब तक 17,168 लोगों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण वालों में 4213 ने आवेदन किया है और अब तक 1880 के यहां सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। मौके पर सीडीओ जुनैद अहमद, एक्सईएन विद्युत ग्रामीण रमाकांत दीक्षित, एक्सईएन रविंद्र कुमार सहित वेंडर्स मौजूद रहे। संवाद